मोबाइल गवर्नेंस परियोजना, 'कर्नाटक मोबाइल वन' के लोकार्पण के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण

बेंगलुरु, कर्नाटक : 08.12.2014

1. मुझे, कर्नाटक सरकार की मोबाइल गवर्नेंस परियोजना 'कर्नाटक मोबाइल वन', के लोकार्पण के लए इस अपराह्न यहां उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। एक समे कत मोबाइल सक्षम सेवा सुपुर्दगी प्रणाली आरंभ करने के इस अग्रणी प्रयास के लए मैं राज्य सरकार की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है क यह देश में अपनी तरह की अद् वतीय पहल है और शासन में नए युग के सूत्रपात का प्रतीक है।

2. यह मोबाइल गवर्नेंस परियोजना, मोबाइल फोन के माध्यम से बिल भुगतान, यातायात चेतावनी, यातायात जुर्माना भुगतान तथा अन्य उपयो गता सु वधाओं जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। यह सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लए 'सकल' नामक प्लेटफार्म के साथ ही शकायतों के त्वरित समाधान भी प्रदान करेगी। यह प्रशंसनीय है क सूचना प्रौद्यो गकी के एक अग्रणी केन्द्र कर्नाटक ने नागरिक-सरकार संबद्धता की नवीन प्र क्रया के निर्माण के लए प्रौद्यो गकी, नवान्वेषण और शासन को आपस में एकीकृत कया है।

3. अच्छा निर्णय लेने के लए नागरिकों सहित, सभी भागीदारों के ज्ञान, अनुभव और वचारों को समे कत करने की जरूरत होती है। शासनकला के इस मंत्र को पहचानते हुए, कर्नाटक द्वारा शासन और शा सत के बीच संबंधों को घनिष्ठ बनाने का प्रयास कया जा रहा है। मेरे लए, यह शासन के उस दर्शन का प्रतीक है जिसका भगवद्गीता,अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादन कया गया था। इन बहुमूल्य ग्रंथों में सरकार और नागरिकों के बीच सहयोगात्मक प्रणाली पर आधारित शासन के उपाय बताए गए हैं।

दे वयो और सज्जनो,

4. नागरिकों की खुशी एक कल्याणकारी राज्य का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। यह वह आधार होता है जिस पर उसके अन्य लक्ष्य निर्भर होते हैं। इसको पूरा करने के लए सुशासन की आवश्यकता होती है, जिसके तहत कानून का शासन, सहभा गतापूर्ण नीति निर्माण, समता, समावे शता, प्रतिसंवेदनात्मकता, पारद र्शता तथा जवाबदेही जैसे पावन तत्व शा मल होते हैं।

5. भारत का सं वधान सुशासन सद्धांतों का मॉडल है। इसकी उद्दे शका, मौ लक अ धकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सद्धांतों में शासन के नियम निहित हैं। ये हमारे देश के मूल्य आधारित

शासन के लए संदर्भ बिन्दु उपलब्ध करवाते हैं। मौ लक अ धकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के वकास तथा मानव गरिमा को कायम रखने के लए आवश्यक है।

6. राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुशासन की रूपरेखा हैं। संसदीय वधान तथा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों ने इन निर्देशकों को शासन के कार्य योग्य बिन्दुओं में बदलने में मदद की है। उदाहरण के लए, कानूनी गारंटी के साथ भोजन, शक्षा और रोजगार के हक से नागरिक सशक्त बने हैं। सभी के लए स्वास्थ्य देखभाल और शक्षा की योजनाओं ने बढ़िया परिणाम दर्शाएं हैं। हाल ही में, सरकार ने पूर्ण वत्तीय समावेशन, डजीटल अवसंरचना के प्रावधान,स्वच्छता अ भयान तथा आदर्श गांवों के निर्माण के लक्ष्य से युक्त अनेक नवान्वेषी योजनाओं के माध्यम से समावेशी वकास को और गति प्रदान की है।

7. जनता की अपेक्षाओं का पूरा होना जन कार्यक्रमों की सफलता का मापदंड है। सुशासन के संदर्भ में इसका अर्थ है कारगर सुपुर्दगी तंत्र की उपलब्धता। नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति प्रतिसंवेदनात्मकता वह चुनौती है जिसका उत्तर हमारे देश के लोक प्रशासकों को ढूंढना होगा। जन संस्थाओं की कारगरता सुपुर्दगी तंत्र तथा नियमों, वनियमों तथा प्र क्रयाओं के संस्थागत ढांचे पर निर्भर करती है। जिसे बदलते समय के साथ, लगातार वक सत होना पड़ेगा। एक ओर जहां सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार के लए संगठनात्मक क्षमताओं में सुधार की जरूरत है वहीं दूसरी ओर पारद र्शता और जवाबदेही में सुधार भी जरूरी है। इससे प्रौद्यो गकी पर आधारित नवान्वेषी समाधानों की जरूरत की महत्व का पता चलता है। एक खगोल-भौतिक वद्, लेखक और वज्ञान वार्ताकार स्वर्गीय कार्ल सैगन ने कहा था, 'हमने एक ऐसी सभ्यता बनाई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व प्रमुखत: वज्ञान और प्रौद्यो गकी पर पूर्णत: निर्भर हैं।'

8. प्रत्येक नागरिक को एक व शष्ट पहचान संख्या प्रदान करते हुए लाभों और सेवाओं की उपलब्धता सुधारने तथा सुगम्यता के लए आधार परियोजना को आरंभ कया गया था। जनवरी, 2013 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में लक्ष्य सुधारने, अप शष्ट समाप्त करने, अ धक पारद र्शता आरंभ करने, आदन-प्रदान लागत कम करने तथा कुशलता बढ़ाने के लए आधार प्रणाली को प्रयोग कया गया। इस पहल ने दर्शाया क कस प्रकार उ चत प्रौद्यो गकी मॉडलों का प्रयोग करते हुए सुशासन के तरीकों को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ई-शासन में शासन मानदंडों में अत्य धक प्रगति की संभावनाएं छुपी हैं। शासन के प्रौद्यो गकी-सघन समाधान आरंभ करने के लए सूचना और संचार प्रौद्यो गकी में भारत की अग्रणी स्थिति से फायदा उठाना समय की जरूरत है।

दे वयो और सज्जनो,

9. सूचना प्रौद्यो गकी में भारी प्रगति ने समाज की कायापलट कर दी है। इसने जन-साधारण के लाभ के लए शासन के क्षेत्र में प्रयोग हेतु प्रौद्यो गकी सक्षम समाधानों के इस्तेमाल के मामले में सरकार के लए एक माहौल तैयार कर दिया है। कर्नाटक एक ऐसा सूचना प्रौद्यो गकी केंद्र है जो सफलता की एक ऐसी कहानी गढ़ रहा है जो बेजोड़ है। यह हमारे देश के कुल सॉफटवेयर निर्यात में तीस प्रतिशत योगदान देता है।

10. राज्य ने न केवल सूचना प्रौद्यो गकी क्षेत्र के वस्तार के लए एक अनुकूल वातावरण नि र्मत कया बल्कि इसने नागरिकों के जीवन से जुड़े सुधारों के लए नवान्वेषण और सरकारी संकल्पना को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है। भू म—जो भू म रिकॉर्ड प्रबंधन की एक ऑनलाइन प्रणाली है, कावेरी—जो स्टांप और पंजीकरण वभाग की एक मूल्यांकन और ई-पंजीकरण प्रणाली है;ई-स्वाथु—एक ऐसा सॉफटवेयर है जो शहरी स्थानीय निकायों में सं पत्तयों को सूचीबद्ध करता है और जिसे अब कावेरी के साथ समे कत कर दिया गया है तथा ई-प्रापण जैसी ई-पहलों ने शासन के मापदंड स्था पत कर दिए हैं। कर्नाटक को ई-शासन के लए सम र्पत स चवालय से युक्त प्रथम भारतीय राज्य होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। मैं शासन में प्रौद्यो गकी को प्रयोग करने के उत्साह के लए आपकी सराहना करता हूं। इस संदर्भ में, मैं 3डी होलोग्राफी, जो एक एक अग्रणी प्रौद्यो गकी है,के प्रदर्शन के साथ जुड़ने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

दे वयो और सज्जनो,

11. मोबाइल फोन ने संचार प्रणाली में कसी अन्य प्रणाली से कहीं अ धक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। यह लोगों को नजदीक लाया है, दूरी कम की है और भौगो लक अलगाव को घटाया है। भारत में 75 प्रतिशत सघनता के साथ मोबाइल फोन ग्राहकों की कुल संख्या 93 करोड़ है। 41 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में 0.76 प्रतिशत मोबाइल फोन ग्राहकों की मा सक वृ द्ध दर शहरी इलाकों के 0.55 प्रतिशत से अ धक है। शासन के नीतिगत परिप्रेक्ष्य से ये आंकड़े उल्लेखनीय हैं।

12. इस वर्ष अगस्त में शुरू कए गए ‘ डजिटल इं डया’ कार्यक्रम में डजिटल ‘सु वधाप्राप्त’ और ‘सु वधाहीन’के बीच के अंतर को पाटते हुए एक डजिटल सशक्त समाज तथा ज्ञानजीवी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का एक अवयव मोबाइल प्लेटफॉर्म से तत्क्षण सरकारी सेवाओं की उपलब्धता है। इस संदर्भ में मैं ‘कर्नाटक मोबाइल वन’ एक बड़ी दूरदृष्टिपूर्ण पहल समझता हूं। यह जानकर प्रसन्नता होती है क लगभग पांच सौ जी2सी (सरकार से नागरिक) और चार हजार से ज्यादा बी2सी (व्यवसाय से ग्राहक)

सेवाएं इस मंच पर समे कत कर दी गई हैं और मुझे बताया गया है क और सेवाओं पर कार्य जारी है। मुझे लगता है क यह सार्थक शासन में बदल जाएगा और ई-शासन को अगले स्तर तक ले जाएगा।

दे वयो और सज्जनो,

13. कर्नाटक नाम, एक व्युत्पत्ति के अनुसार 'कारू नाडू' से निकला है। मुझे उम्मीद है क अपने अर्थ 'उन्नत भू म' के अनुरूप यह राज्य अपने ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करता रहेगा। तेजी से बदल रही दुनिया में वद्यार्थी, अन्वेषक और कार्य करने वाले ही नागरिकों के लए एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आपने अपने प्रयासों के माध्यम से यह दर्शा दिया है और मैं इसके लए आपकी सराहना करता हूं। अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट न हो जाएं; शासन में सुधार के अपने प्रयास जारी रखें। मैं इसी वचार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं क बेहतर भ वष्य के निर्माण के लए वर्तमान में रचनात्मकता जरूरी है। मैं मोबाइल गवर्नेंस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद,

जयहिन्द !